



KHAN GLOBAL STUDIES

KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

Day-03

Dr. Bharat Sir

प्रश्न: उन कारकों का विश्लेषण करें जिन्होंने बिहार को भारत में सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक के रूप में उभरने में योगदान दिया है, साथ ही इसकी आर्थिक प्रगति में बाधा डालने वाली लगातार चुनौतियों का भी समाधान किया है।

उत्तर: बिहार, जिसे कभी भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक माना जाता था, ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास देखा है, जो देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है। इस वृद्धि को कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

बिहार के आर्थिक विकास को संचालित करने वाले कारक

➤ बिहार हाल के वर्षों में भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक बनकर उभरा है, जिसने पिछले पांच वर्षों में 11% से अधिक की औसत जीडीपी वृद्धि दर हासिल की है। इस प्रभावशाली वृद्धि का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

1. अनुकूल सरकारी नीतियाँ: बिहार सरकार ने निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार और पहल लागू की हैं। इसमें शामिल है:
 - व्यवसायों के लिए विनियामक प्रक्रिया को सरल बनाना
 - कर कम करना
 - बुनियादी ढांचे में सुधार
 - कृषि और उद्योग के लिए सब्सिडी प्रदान करना
2. प्रचुर प्राकृतिक संसाधन: बिहार भूमि, जल और खनिज सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यह आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
3. युवा और कुशल कार्यबल: बिहार में युवा और कुशल कार्यबल है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी संपत्ति है।
4. बढ़ती प्रयोज्य आय: बिहार में प्रयोज्य आय बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ता खर्च बढ़ रहा है।

लगातार चुनौतियाँ आर्थिक प्रगति में बाधा बन रही हैं

➤ अपनी प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद, बिहार को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी आर्थिक प्रगति में बाधक हैं। इन चुनौतियों में शामिल हैं:

1. बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ: सड़क, बिजली और सिंचाई सहित बिहार का बुनियादी ढाँचा अविकसित है, जिससे

आर्थिक गतिविधि में बाधा आ रही है।

2. कौशल अंतर: बिहार के कार्यबल के कौशल और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच बेमेल है, जिससे रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं।
3. गरीबी और असमानता: बिहार में गरीबी और असमानता का स्तर उच्च है, जो समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक चुनौती है।
4. वित्त तक पहुँच: बिहार में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को वित्त तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी विकास क्षमता सीमित हो जाती है।
5. कमजोर शासन: भ्रष्टाचार और अक्षमता जैसे शासन संबंधी मुद्दे, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालते हैं।

चुनौतियों का समाधान करना और विकास को कायम रखना

➤ इन चुनौतियों से निपटने और अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए, बिहार को निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है:

1. बुनियादी ढाँचा विकास: कनेक्टिविटी बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सड़क, बिजली, सिंचाई और डिजिटल कनेक्टिविटी सहित बुनियादी ढाँचे के विकास में भारी निवेश करें।
2. कौशल विकास: कार्यबल के कौशल को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम लागू करें।
3. गरीबी निर्मूलन: समावेशी विकास को बढ़ावा देने और असमानता को कम करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने सहित लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करें।
4. वित्तीय समावेशन: एसएमई और हाशिए पर रहने वाले समूहों को उनके विकास और अर्थव्यवस्था में योगदान का समर्थन करने के लिए ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना।
5. शासन को सुदृढ़ बनाना: व्यापार वृद्धि और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने सहित शासन में सुधार के उपाय लागू करें।

➤ इन चुनौतियों का समाधान करके और प्रभावी रणनीतियों को लागू करके, बिहार आर्थिक विकास और प्रगति के अपने पथ पर आगे बढ़ सकता है, टिकाऊ और समावेशी विकास प्राप्त कर सकता है जिससे उसके सभी नागरिकों को लाभ होगा।

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव का विश्लेषण करें, ट्रांसमिशन चैनलों की जांच करें और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के उपायों का प्रस्ताव करें।

उत्तर: वैश्विक अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में मंदी का सामना कर रही है, मुख्य रूप से ब्रेटव-19 महामारी, यूक्रेन में चल रहे युद्ध और बढ़ती मुद्रास्फीति जैसे कारकों के कारण। इस वैश्विक मंदी का भारत की अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिससे इसकी वृद्धि, व्यापार और वित्तीय बाजार प्रभावित हुए हैं।

वैश्विक आर्थिक मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

➤ चल रही वैश्विक आर्थिक मंदी, जिसमें आर्थिक वृद्धि में कमी, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाएं शामिल हैं, ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। जिन ट्रांसमिशन चैनलों के माध्यम से वैश्विक मंदी भारत को प्रभावित करती है उनमें शामिल हैं:

1. **निर्यात मांग में कमी:** जैसे-जैसे वैश्विक मांग कमजोर होती जा रही है, भारतीय निर्यात को कम मांग का सामना करना पड़ सकता है, जिससे निर्यात-उन्मुख उद्योग और समग्र आर्थिक विकास प्रभावित होगा।
2. **पूंजी बहिर्प्रवाह:** जैसे-जैसे वैश्विक जोखिम की भूख कम होती जा रही है, निवेशक भारत से धन निकाल सकते हैं, जिससे पूंजी का बहिर्प्रवाह होगा और भारतीय रुपये पर दबाव पड़ेगा।
3. **उच्च उधार लागत:** वैश्विक मौद्रिक सख्ती से भारत के लिए उधार लेने की लागत बढ़ सकती है, जिससे सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के वित्त प्रभावित होंगे।
4. **व्यापार घर्षण:** प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते व्यापार तनाव और संरक्षणवादी उपाय भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित कर सकते हैं, जिससे आयात पर निर्भर उद्योगों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ सकता है।

वैश्विक आर्थिक मंदी का बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

➤ वैश्विक आर्थिक मंदी का भी बिहार की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, विशेष रूप से कृषि पर इसकी निर्भरता और इसकी अपेक्षाकृत कम विविध अर्थव्यवस्था को देखते हुए। ट्रांसमिशन चैनलों में शामिल हैं:

1. **कृषि मूल्यों में कमी:** कृषि वस्तुओं की कम वैश्विक मांग से बिहार के कृषि उत्पादों की कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण आजीविका प्रभावित होगी।

2. **कम प्रेषण:** चूंकि प्रेषण भेजने वाले देशों में आर्थिक गतिविधि धीमी हो गई है, इसलिए बिहार में प्रेषण में गिरावट आ सकती है, जिससे घरेलू आय और उपभोग व्यय प्रभावित होगा।
3. **कम निवेश:** बुनियादी ढांचे और अन्य विकास परियोजनाओं में कम निवेश बिहार की आर्थिक विकास संभावनाओं में बाधा बन सकता है।
4. **नौकरी के नुकसान:** निर्यात-उन्मुख उद्योगों में मंदी और कम निवेश से बिहार में नौकरियां खत्म हो सकती हैं, जिससे रोजगार के अवसर और समग्र आर्थिक कल्याण प्रभावित हो सकता है।

नकारात्मक प्रभावों को कम करना

➤ वैश्विक आर्थिक मंदी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, भारत और बिहार सरकारें कई उपाय लागू कर सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. **घरेलू मांग को बढ़ावा देना:** घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के उपायों को लागू करें, जैसे बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाना, उपभोक्ताओं के लिए कर छूट प्रदान करना और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों का समर्थन करना।
 2. **निर्यात को बढ़ावा देना:** निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करके, व्यापार रसद में सुधार और निर्यात बाजारों में विविधता लाकर निर्यात को प्रोत्साहित करें।
 3. **निवेश आकर्षित करना:** निवेश आकर्षित करने के लिए सुधार लागू करें, जैसे नियामक प्रक्रिया को सरल बनाना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और निवेशकों के लिए सब्सिडी या कर छूट प्रदान करना।
 4. **कौशल विकास:** कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाने और उन्हें आर्थिक झटकों के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करें।
 5. **वित्तीय समावेशन:** आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने और भेद्यता को कम करने के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और ग्रामीण परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करें।
 6. **राजकोषीय अनुशासन:** सरकारी उधारी को सीमित करने और स्थिर व्यापक आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखें।
 7. **सामाजिक सुरक्षा जाल:** कमजोर आबादी को मंदी के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों और रोजगार सहायता योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करें।
- इन उपायों को लागू करके, भारत और बिहार दोनों सरकारें वैश्विक आर्थिक मंदी के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकती हैं और सतत आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे सकती हैं।

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास पथ का तुलनात्मक विश्लेषण करें, उन कारकों की जांच करें जिनके कारण विकास दर में अंतर आया है और उन सबक की पहचान की जा रही है जो बिहार भारत के अन्य उच्च विकास वाले राज्यों से सीख सकता है।

उत्तर: विकास पथों का तुलनात्मक विश्लेषण पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरी है। हालाँकि, भारत के पूर्वी राज्यों में से एक, बिहार की विकास गति अधिक धीमी रही है, जहाँ विकास दर राष्ट्रीय औसत से पीछे है। इस तुलनात्मक विश्लेषण का उद्देश्य उन कारकों की जांच करना है जिन्होंने इन अलग-अलग विकास पैटर्न में योगदान दिया है और उन सबक की पहचान की है जो बिहार भारत के अन्य उच्च विकास वाले राज्यों से सीख सकता है।

विभेदक विकास दर को चलाने वाले कारक

➤ भारत और बिहार के अलग-अलग विकास पथ में कई कारकों ने योगदान दिया है। इन कारकों को मोटे तौर पर आर्थिक, सामाजिक और शासन-संबंधी पहलुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है।

आर्थिक कारक:

- 1. आर्थिक संरचना:** भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से बढ़ते सेवा क्षेत्र के साथ अधिक विविध अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर चुकी है। दूसरी ओर, बिहार कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे यह कृषि कीमतों और मौसम की स्थिति में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है।
- 2. बुनियादी ढांचे का विकास:** भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास, विशेषकर परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, लेनदेन लागत कम हुई है और पूरे देश में आर्थिक गतिविधि सुगम हुई है। बिहार का बुनियादी ढांचा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अविकसित है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में बाधा आती है।
- 3. कौशल विकास:** भारत ने कार्यबल के कौशल को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया है। बिहार के कौशल विकास प्रयास कम व्यापक रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उपलब्ध कौशल और उद्योगों द्वारा मांगे गए कौशल के बीच बेमेल है।

सामाजिक परिस्थिति:

- 1. साक्षरता और शिक्षा:** भारत ने साक्षरता दर और शैक्षिक प्राप्ति के स्तर में सुधार लाने में पर्याप्त प्रगति की है। बिहार की साक्षरता दर और शैक्षिक परिणाम राष्ट्रीय औसत से पीछे

हैं, जिससे कार्यबल की क्षमता सीमित हो गई है और नवाचार और उद्यमिता में बाधा आ रही है।

- 2. स्वास्थ्य देखभाल:** भारत ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार के लिए विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम लागू किए हैं। बिहार का स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा और सेवाएँ अपर्याप्त हैं, जिससे इसके कार्यबल के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर असर पड़ रहा है।

शासन-संबंधी कारक:

- 1. नियामक पर्यावरण:** भारत ने नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कारोबारी माहौल में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। बिहार का नियामक ढांचा व्यवसायों के लिए अधिक बोझिल और समय लेने वाला हो सकता है, जो निवेश और उद्यमिता को हतोत्साहित कर सकता है।
- 2. प्रशासनिक दक्षता:** भारत की प्रशासनिक मशीनरी में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुधार किए गए हैं। बिहार को प्रशासनिक दक्षता में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में देरी होती है।

उच्च विकास वाले राज्यों से सबक

- कई भारतीय राज्यों ने बिहार की तुलना में उच्च आर्थिक विकास दर हासिल की है। ये राज्य बिहार को अपनी आर्थिक प्रगति में तेजी लाने के लिए मूल्यवान सबक प्रदान कर सकते हैं:
- 1. गुजरात:** बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल विकास और औद्योगिक प्रोत्साहन पर गुजरात का ध्यान इसकी सफलता की कुंजी रहा है। बिहार अपनी आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इन रणनीतियों को दोहरा सकता है।
 - 2. तमिलनाडु:** शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक कल्याण पर तमिलनाडु के मजबूत फोकस ने आर्थिक विकास और समावेशी विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। बिहार अपने सामाजिक बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी में सुधार के लिए समान दृष्टिकोण अपना सकता है।
 - 3. कर्नाटक:** सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों को आकर्षित करने में कर्नाटक की सफलता ने इसे प्रेरित किया है।
- बिहार भारत के अन्य उच्च विकास वाले राज्यों, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक से मूल्यवान सबक सीख सकता है, जिन्होंने तेजी से आर्थिक प्रगति हासिल की है। इन पाठों में शामिल हैं:
- 1. आर्थिक विविधीकरण पर ध्यान:** कृषि पर निर्भरता कम करने और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए विनिर्माण, सेवाओं और पर्यटन जैसे गैर-कृषि क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना।
 - 2. बुनियादी ढांचे में निवेश:** कनेक्टिविटी में सुधार, लेनदेन लागत को कम करने और आर्थिक गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष रूप से परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देना।

3. **कौशल विकास को बढ़ाना:** कार्यबल के कौशल को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए लक्षित कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करना।
4. **साक्षरता और शिक्षा में सुधार:** साक्षरता दर में सुधार करने, शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने और एक कुशल कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करना।
5. **स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना:** कार्यबल के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना।
6. **विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:** निवेश और उद्यमशीलता को आकर्षित करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, नौकरशाही बाधाओं को कम करना और कारोबारी माहौल में सुधार करना।
7. **प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना:** प्रशासनिक दक्षता में सुधार, प्रक्रियात्मक देरी को कम करना और नीतियों और कार्यक्रमों का पारदर्शी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- इन रणनीतियों को अपनाकर और उच्च विकास वाले राज्यों के अनुभवों से सीखकर, बिहार अपनी आर्थिक वृद्धि को तेज कर सकता है और राष्ट्रीय औसत के साथ अंतर को पाट सकता है।

